भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1618

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

7 श्रावण, 1948 (शक)

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

1618. डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन देशों की संख्या कितनी है जिनके साथ भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) या सहयोग समझतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों तथा ऐसे सभी समझौतों का ब्यौरा क्या है;
(ख) भागीदार देशों में भारत की डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और क्षमता-निर्माण पहलों के उपयोग सहित उक्त समझौतों के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;
(ग) भागीदार देशों तथा संबंधित मंत्रालयों एवं अभिकरणों के साथ डीपीआई भागीदारी के समन्वय हेतु क्या संस्थागत ढांचा अपनाया गया है; और
(घ) आगामी तीन वर्षों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर विशेषकर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूपरेखा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** पिछले एक दशक में, भारत सरकार ने खुले, अंतर-संचालित और समावेशी डिजिटल प्लेटफार्मों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जिसने सार्वजनिक सेवा वितरण को बदल दिया है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और नागरिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। सरकार का दृष्टिकोण अब विश्व स्तर पर जुड़े, विश्वसनीय और समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में घरेलू डिजिटल परिवर्तन से आगे बढ़ गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्युजी) की बैठकों के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक था। जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा ने डीपीआई को आर्थिक विकास के लिए विकास उत्प्रेरक के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, **भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए सफल जनसंख्या-पैमाने के डिजिटल समाधानों को साझा करने में सहयोग के लिए**

24 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण, ज्ञान और श्रेष्ठ पद्धतियों के आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यशालाओं और विशेषज्ञ परामर्श, व्यवहार्यता और ई-तत्परता आकलन, और सिद्ध डिजिटल समाधानों के विकास, संचालन और स्केलिंग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की देश-वार सूची **अनुलग्नक-I में दी गई है।**

भारत सरकार ने इंडिया स्टैक और अन्य जनसंख्या-पैमाने के डिजिटल समाधानों को प्रदर्शित करने और रुचि के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भागीदार देशों के साथ वर्चुअल परामर्श और तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की हैं। पहचाने गए समाधानों के आधार पर, भागीदार देश के डिजिटल इकोसिस्टम की तैयारी का आकलन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन सहित संबंधित भारतीय तकनीकी एजेंसियों और भागीदार देशों के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा की गई है। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है, जिसमें डिजीलॉकर के कार्यान्वयन के लिए केन्या के साथ कार्यान्वयन फ्रेमवर्क समझौते (आईएफए) और एक गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) करना शामिल है। क्यूबा में एक मूलभूत डिजिलॉकर समाधान का विकास भी शुरू हो गया है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत, दिसंबर 2025 में क्यूबा के प्रतिनिधिमंडल के लिए डीपीआई पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ई-संजीवनी, ई-ऑफिस, ई-हॉस्पिटल आदि सहित प्रमुख भारतीय डिजिटल समाधानों को संभावित रूप से अपनाने के लिए लाओ पीडीआर, सेशेल्स, वेनेजुएला, आर्मेनिया, फिजी, गुयाना कोलंबिया जैसे भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्श आगे बढ़ा है। इसके अलावा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) विभिन्न देशों की भुगतान प्रणालियों से जुड़ा हुआ है ताकि व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) प्रेषण और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) लेनदेन की सुविधा मिल सके। भागीदार संस्थानों के साथ यूपीआई का उपयोग करने वाले देशों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

सरकार विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए नियमित रूप से अध्ययन दौरों और तकनीकी बातचीत की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक) आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ जुड़ सकें। इन मुलाकातों से पार्टनर देशों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। हाल की कुछ स्टडी विज़िट में केन्या, रवांडा, नेपाल, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं।

सरकार ने सोशल इम्पैक्ट फंड (एसआईएफ) को भी मंजूरी दे दी है, जो विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में ग्लोबल साउथ में डीपीआई पायलट कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के नेतृत्व में, बहु-हितधारक पहल है।

*****

अनुलग्नक-I

हस्ताक्षरित इंडिया स्टैक समझौता ज्ञापनों के भागीदार देशों की सूची

क्र.सं.	**प्राप्तकर्ता देश**	**हस्ताक्षर करने की तिथि**
1	एंटीगुआ और बारबुडा की सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिताएँ और ऊर्जा मंत्रालय	13 जून, 2023
2	आर्मेनिया गणराज्य का उच्च तकनीक उद्योग मंत्रालय	12 जून, 2023
3	पापुआ न्यू गिनी का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय	28 जुलाई, 2023
4	सिएरा लियोन गणराज्य का सूचना और संचार मंत्रालय	12 जून, 2023
5	सूरीनाम गणराज्य का आर्थिक कार्य, उद्यमिता एवं तकनीकी नवाचार मंत्रालय	12 जून, 2023
6	त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य का डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय	11 अगस्त, 2023
7	तंजानिया संयुक्त गणराज्य का सूचना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	09 अक्टूबर, 2023
8	केन्या गणराज्य का सूचना, संचार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय	05 दिसंबर, 2023
9	क्यूबा गणराज्य का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	19 जनवरी, 2024
10	कोलंबिया गणराज्य का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16 फरवरी, 2024
11	लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओ पीडीआर) का प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय	27 जुलाई, 2024

12	सेंट क्रिस्टोफर (सेंट किट्स) और नेविस फेडरेशन की सरकार	05 अगस्त, 2024
13	इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का सूचना नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन	30 सितंबर 2024
14	जमैका के प्रधान मंत्री का कार्यालय	01 अक्टूबर, 2024
15	गाम्बिया गणराज्य का संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय	03 अक्टूबर, 2024
16	फिजी गणराज्य का व्यापार, सहकारिता, लघु और मध्यम उद्यम और संचार मंत्रालय	12 नवंबर 2024
17	गुयाना के सहकारी गणराज्य के प्रधान मंत्री का कार्यालय	19 नवंबर 2024
18	वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पीपुल्स पावर मंत्रालय	12 फरवरी 2025
19	श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय	5 अप्रैल 2025
20	ब्राजील संघीय गणराज्य का सार्वजनिक सेवाओं में प्रबंधन और नवाचार मंत्रालय	8 जुलाई 2025
21	लेसोथो किंगडम का सूचना, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय	21 जुलाई 2025
22	मालदीव गणराज्य का होमलैंड सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	24 जुलाई 2025
23	मंगोलिया का डिजिटल विकास, नवाचार और संचार मंत्रालय	13 अक्टूबर 2025
24	सेशेल्स गणराज्य का सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग	8 फरवरी 2026

अनुलग्नक-II

भागीदार संस्थानों के साथ यूपीआई का उपयोग करने वाले देश

क्र. सं.	**देश का नाम**	**के लिए लाइव**	**भागीदार संस्थान**	**से लाइव**
1.	भूटान	पी2एम	आरएमए भूटान	जुलाई 2021
2.	फ़्रांस	पी2एम	एलवाईआरए नेटवर्क	फरवरी 2024
3.	मॉरीशस	पी2एम	बैंक ऑफ मॉरीशस	फरवरी 2024
4.	नेपाल	पी2एम	फोन पे पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	मार्च 2024
		पी2पी	नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)	जून 2026
5.	कतर	पी2एम	कतर नेशनल बैंक	सितंबर 2025
6.	सिंगापुर	पी2एम	एनईटीएस सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड, हिटपे पेमेंट्स सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड। लिक्विडपे ग्रुप पीटीई. लिमिटेड	अगस्त 2021
		पी2पी	बीसीएस पे नाउ	फरवरी 2023
7.	श्रीलंका	पी2एम	लंका पे प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी 2024
8.	संयुक्त अरब अमीरात	पी2एम	मशरेक बैंक पीएससी (नियो पे) नेटवर्क इंटरनेशनल मैग्नाटी- एकल स्वामित्व एलएलसी	अप्रैल 2022
9.	कंबोडिया	पी2एम	एक्लेडा बैंक पीएलसी	जून 2026
10.	यूनान	पी2पी	यूरोबैंक एस.ए	मई 2026

******